



डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ गैर कानूनी घोषित

अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया

वॉशिंगटन डीसी, 20 फरवरी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप द्वारा लगाए गए बड़े पैमाने पर टैरिफ (आयात शुल्क) गैरकानूनी हैं।

कोर्ट ने कहा कि ट्रंप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईपीए) का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के रूप में असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं रखते।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखी कि यह कानून आपात स्थिति के लिए है, न कि टैरिफ लगाने के लिए। यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीति को गहरा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने कई देशों पर आपातकाल के नाम पर भारी टैरिफ थोपे थे।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति असीमित और एकतरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने के लिए साफ तौर पर संसदीय अनुमति

जरूरी है। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की विदेश नीति और आर्थिक एजेंडे पर सीधा वार है।

गौरतलब है कि पिछले साल इसी कंजरवेटिव झुकाव वाली अदालत ने इमिग्रेशन, एजेंसी हैड्स की बर्खास्तगी और सरकारी खर्च में कटौती जैसे मामलों में ट्रंप का साथ दिया था। ऐसे में यह फैसला और भी अहम माना जा रहा है।

ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी कि अगर कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कंपनियों और देशों के निवेश दावों को जोड़ दिया जाए तो बोझ खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है।

डॉनल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीते साल अगस्त में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप के कदम को गैरकानूनी करार दे दिया था, लेकिन अदालत ने टैरिफ को लागू रहने

- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा भारी झटका दिया और कहा कि ट्रंप को इन्टरनैशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि यह कानून आपात स्थिति के लिए है, न कि टैरिफ लगाने के लिए।
- चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति एकतरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा करते हैं, पर, इसके लिए संसदीय अनुमति की जरूरत है।
- सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि उन्होंने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं।
- ट्रंप ने इस मसले पर जनवरी में कहा भी था, अगर कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं।
- हालांकि कोर्ट के आदेश से सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर अलग कानूनों के तहत टैरिफ लगाए गए थे, जो अभी कायम रहेंगे, लेकिन रैसिप्रोकल टैरिफ, दंडात्मक टैरिफ खत्म कर दिए गए हैं।

दिया था। इसके बाद वाइट हाउस की ओर से अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन को झटका दे दिया था, लेकिन अदालत ने टैरिफ को लागू रहने

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट ने ट्रंप के वकीलों की दलील को नहीं माना और टैरिफ रद्द

करने का फैसला सुनाया। यह मामला डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे का पहला बड़ा मुद्दा है, जो सीधे सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है।

कोर्ट के आदेश से ट्रम्प के सभी

इस फैसले से भारत पर तुरंत क्या असर होगा

जयपुर, (का.सं.), 20 फरवरी। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द करने के फैसले का मतलब है कि भारत से अमेरिका को होने वाले 55 प्रतिशत निर्यात पर 18 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफ नहीं लगेगा।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार,

अमेरिका की सर्वोच्च अदालत के फैसले से भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जीटीआरआई के एक विश्लेषण के अनुसार, "पारस्परिक टैरिफ को हटाने से अमेरिका को होने वाले भारत के लगभग 55 प्रतिश निर्यात 18 प्रतिशत शुल्क से मुक्त हो जाएंगे, और उन पर केवल मानक

एमएफएन टैरिफ ही लागू होंगे।" थिंक टैंक के अनुसार, कुछ पेचिदगियां मौजूद हैं। इस वजह से इस्पात और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत और कुछ ऑटो घटकों पर 25 प्रतिशत रहेगी। निर्यात मूल्य के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से वाले उत्पाद, जिनमें स्मार्टफोन, पेट्रोलियम उत्पाद और दवाइयां आदि अमेरिकी टैरिफ से मुक्त रहेंगे।

‘मेरे नाम से ही आए दिन नई साइट बन जाती हैं, मेरे फोटो अपलोड हो जाते हैं

जयपुर आए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा

जयपुर, 20 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि उनके नाम से आए दिन नई साइट बन जाती हैं और उसमें मेरे फोटो अपलोड हो जाते हैं। इसी तरह की साइट से मेरी बेटी और बहन को मैसेज भेजे गए, लेकिन वो उनकी भाषा समझ गई। जब मैंने इसकी शिकायत साइबर पुलिस में की तो पता चला कि ये सभी साइट्स नाइजीरिया में बन रही हैं।

सीजेआई ने यह विचार शुक्रवार को आरआईसी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि पहले सोचो, फिर बोलो, पहले विचार करो, फिर काम करो। डिजिटल अपराध

- जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया और कहा, साइबर फ्राँड से 50,000 करोड़ रुपए तक ठगे गए हैं और करीब 66 लाख शिकायतें लंबित चल रही हैं।

से बचने के लिए हमें इसी को अमल में लाना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध इस चिंताजनक हालत तक बढ़ गया है कि साइबर फ्राड से पचास हजार करोड़ रुपए ठगे गए हैं और करीब 66 लाख शिकायतें लंबित चल रही हैं। सीजेआई ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए आपसी समन्वय से काम करना होगा। “हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल तरीके से फ्राँड कर अदालती दस्तावेज तक बन रहे हैं। ऐसे में जल्द ही कि सभी मिलजुलकर इससे लड़ने के लिए खड़े हों।”

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि तकनीक दोधारी तलवार बन चुकी है। एक तरफ डिजिटल तकनीक का अपना फायदा है तो दूसरी तरफ हमें सचेत रहना भी जरूरी है।

साइबर सुरक्षा आज के समय की मांग है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में साइबर स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आज से दस साल पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान के विनोद जाखड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 फरवरी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व

- विनोद जाखड़ को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का करीबी माना जाता है।

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबी विनोद जाखड़ को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया।

यह पहला अवसर है, जब राजस्थान के किसी नेता को इस पद पर नियुक्त किया गया है।

एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक प्रेस विज्ञापित में कहा, पार्टी निर्वर्तमान अध्यक्ष वरुण चौधरी, जो बिहार से हैं, के योगदान को सराहना करती है।

हिंदुओं के तीन बच्चे होने मुद्दे पर शंकराचार्य ने भागवत का विरोध किया

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, समाज की प्रगति ज्यादा संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति व धार्मिक मूल्यों के आधार पर होती है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 फरवरी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिंदू दंपतियों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने के आह्वाण को बकवास बताते हुए कहा कि समाज केवल संख्या के आधार पर न तो जीवित रहता है और न ही प्रगति करता है, बल्कि उसकी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक मूल्यों से उसका अस्तित्व और विकास तय होता है। उन्होंने तर्क दिया, “कुलों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो सब भाग जाते हैं।”

शंकराचार्य हाल के समय में भाजपा और आरएसएस नेताओं की आलोचना करते रहे हैं, विशेषकर जनवरी में प्रयागराज की घटना के बाद, जब जिला प्रशासन ने उनकी पालकी रोक दी थी और उन्हें संगम में स्नान के लिए पालकी से उतरकर, पैदल जाने

- शंकराचार्य ने कहा, ज्यादा बच्चे हों, पर उन्हें संस्कारों व मूल्यों का पाठ ना पढ़ाया जाए तो समाज प्रगति नहीं करता।
- ज्ञातव्य है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हिंदुओं के तीन बच्चे होने ही चाहिए।

को कहा था। पिछले कुछ सप्ताहों में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर तीखे विचार व्यक्त किए हैं, जो प्रायः आरएसएस और भाजपा के प्रति आलोचनात्मक रहे हैं।

इस बार उन्होंने भागवत द्वारा लखनऊ में इस सप्ताह की गई उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने नवविवाहित दंपतियों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने का आा न किया था। भागवत ने कहा था कि विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाना और

सामाजिक दायित्व निभाना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि बिना उचित संस्कार दिए केवल अधिक बच्चे पैदा करने से समाज मजबूत नहीं होगा। उन्होंने कहा, “माता-पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ बड़े हों, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म पर अडिगर रह सकें। सौ तारे उतनी रोशनी नहीं देते, जितनी एक चाँद देता है।”

शंकराचार्य ने आगे चेतावनी दी कि (हिंदू समाज के भीतर) आंतरिक संघर्ष

उसे कमजोर कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण के वंशजों का उदाहरण दिया, जो बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक कलह से नष्ट हुए थे। “जब संख्या एकता और मूल्यों के बिना बढ़ती है, तो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं।”

दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी भागवत की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है और इसका राजनीतिकरण करने के बजाय, सभी समुदायों को इस पर जिम्मेदारी के साथ, विचार और चर्चा करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी संसाधनों पर दबाव डाल रही है और अनेक परिवार, जिनमें मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं, बढ़ते खर्च और शिक्षा की लागत के कारण कम बच्चे पैदा करने का निर्णय ले रहे हैं।

भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘‘पैक्स सिलिका’’ गठबंधन की सदस्यता ली

पैक्स सिलिका का गठन दुर्लभ खनिजों और सेमीकंडक्टर्स पर चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए किया गया था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 फरवरी। चीन के सेमीकंडक्टर और दुर्लभ खनिजों पर एकाधिकार को तोड़ने के ठोस प्रयास में भारत आज औपचारिक रूप से अमेरिका-नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया। यह केवल एक तकनीकी साझेदारी से कहीं अधिक का संकेत है। ऐसे समय में जब सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखलाएँ आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक स्वायत्तता को आकार दे रही हैं, नई दिल्ली ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित करने और उन्नत विनिर्माण में कमजोरियों को कम करने के उद्देश्य से बने इस समूह में कदम रखा है।

इसी बीच, आर्थिक मामलों के लिए अमेरिकी अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने

- भारत के इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैक्स सिलिका में भारत के प्रवेश एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा, भारत में एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम उभर रहा है और पैक्स सिलिका इसके लिए जरूरी है, भारत के युवा वर्ग को इससे फायदा होगा।
- अमेरिका के अंडर सैक्रेटरी (इकोनॉमिक अफेयर्स) जैकब हैलबर्ज ने कहा कि जिस तरह से एक प्रमुख भारतीय शहर की दूसरे देश ने सायबर गड़बड़ी कर लाइट्स बंद कर दी थी, वह चेतावनी थी कि भारत को इस गठबंधन में आ जाना चाहिए।
- हैलबर्ज असल में 12 अक्टूबर 2020 में मुम्बई हुए पावर कट का हवाला दे रहे थ, कहा जाता है कि यह चीन की साइबर शरारत थी।
- एक बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर के दुर्लभ खनिज उत्पादन का 61 प्रतिशत व उनके संवर्धन का 92 प्रतिशत चीन के नियंत्रण में है और इससे दुनिया के अन्य बड़े देशों से सौदेबाजी में चीन का पलड़ा भारी रहता है। ज्ञातव्य है कि सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर इलैक्ट्रिक वाहनों तक सभी में दुर्लभ खनिजों का प्रयोग होता है।

कहा, “सीमा पार से एक की-स्ट्रोक द्वारा एक महान भारतीय शहर की

बतियाँ बुझा दी गईं” और यह नई दिल्ली के लिए इस समूह में शामिल होने का

पर्याप्त संकेत था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फिर से राजस्थान हाई कोर्ट को बम की धमकी

जयपुर, 20 फरवरी। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई।

- ई-मेल पर भेजी धमकी में सीजेआई का दौरा रद्द करवाने और 12 बजे तक हाई कोर्ट खाली करने की चेतावनी दी गई थी और कहा था कि कोर्ट में आरडीएक्स लगाया गया है। पर, जाँच व तलाशी में कुछ भी नहीं मिला।

इस बार धमकी भरे मेल में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत के दौरे को रद्द करने की चेतावनी दी गई थी। मेल में लिखा था कि सीजेआई का दौरा कैसिल

रील के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित की नियुक्ति रद्द करने पर अंतरिम रोक

-यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर, 20 फरवरी। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित की नियुक्ति को रद्द किए जाने के एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा और संगीता शर्मा को खंडपीठ ने यह आदेश इस मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। सुनवाई के दौरान मूल याचिकाकर्ता डॉ पुरुषोत्तम नारायण शर्मा की ओर से अदालत को कहा गया कि रील के प्रबंध निदेशक के चयन के लिए गठित बोर्ड में राज्य के मुख्य सचिव का होना आवश्यक है, क्योंकि रील में 49 प्रतिशत स्ट्रेक रीको का है और रीको राजस्थान सरकार की एक कंपनी है, यानी यह 49 प्रतिशत प्रतिशत भागीदारी राजस्थान सरकार की ही है। उनकी तरफ से कहा गया कि इस संदर्भ में स्पष्ट गाइडलाइन भी है, जो यह कहती है कि किसी भी इकाई या कंपनी, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी हो, उसमें राज्य सरकार का पक्ष व हित देखने के लिए मुख्य सचिव पक्षकार होंगे और उनके पक्ष को सुने बगैर वरिष्ठ अफसरों या अधिकारी, जैसे किसी

- केन्द्र सरकार तथा दीक्षित की ओर से अदालत में कहा गया कि “रील मे रीको मात्र 49 फीसदी की निवेशक है, उसका हिस्सा राज्य सरकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता। रील के प्रबंध निदेशक की चयन प्रक्रिया में कभी भी राज्य के मुख्य सचिव को पक्षकार नहीं बनाया गया।”
- सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा ने भी यह टिप्पणी की कि गाइडलाइन केवल एक दिशा सूचक की तरह कार्य करती है, परंतु वह एक नियम या कानून नहीं है।

कंपनी के अध्यक्ष अथवा एम डी, की नियुक्ति नहीं की जा सकती। वहीं अपीलार्थी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए के शर्मा और मुख्य कासलीवाल की ओर से कहा गया कि उक्त मामले के संदर्भ में रीको को राज्य सरकार का पक्षकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि रीको एक सरकारी कंपनी अवश्य है और उसके कर्मचारियों, अधिकारियों व प्राइवेट पार्टी किसी संवैधानिक अधिकार की पालना करने हेतु दायर रिट याचिका के मामलों में रीको को सरकार की परिभाषा

में ले सकती है, क्योंकि अंततः ऐसे मामलों में राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को ही अदालत कानून की पालना करने के लिए आदेश दे सकती है, परंतु अन्य व्यवसायिक अनुबंधन के मामलों में रीको एक प्राइवेट कंपनी की भांति ही है, जिसको राज्य सरकार का विभाग नहीं माना जा सकता। इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल व वरिष्ठ अधिवक्ता भरत व्यास ने भी अदालत को यही तर्क

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

बच्चों को शिक्षा के साथ यह भी सिखाया जाना चाहिए कि वह मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं, संपूर्ण राष्ट्र की थाती हैं। —स्वामी रामदेव

मोबाइल से बढ़ता मानसिक बीमारियों का खतरा

आज के दौर में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम उनकी मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सेल और ध्यान भटकाने वाले बनते जा रहे हैं। एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था सेपियनलैब्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, कम उम्र में जब बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाते हैं तो युवावस्था आते-आते उनके दिमाग पर विपरीत असर दिखने लगता है। यह रिपोर्ट 40 देशों के 2,76,969 युवाओं से बातचीत करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन दिए गए, उनमें आत्महत्या के विचार, दूसरों के प्रति गुस्सा, सच्चाई से दूर रहना और हेलोसिनेशन होना शामिल है। लीलावती अस्पताल, मुंबई के मनोचिकित्सक डॉ. शोरुक मोटवानी बताते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम, ट्रॉमा और हिंसा देखने से बच्चों में आक्रामकता, डिप्रेशन और चिंता विकार बढ़ रहे हैं। वहीं, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. समीरा एस राव का कहना है कि स्क्रीन टाइम अधिक होने से बच्चों का मूडस्विंग्स, सिरदर्द और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

भारत में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के बेज़ा इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग अब जोर शोर से उठने लगी है। भारत सरकार ने भी देर आये दुरस्त आये अब सोशल मीडिया के बेज़ा इस्तेमाल से बच्चों को बचाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आर्थिक सर्वे में इस पर भारी चिंता व्यक्त की गई थी। इसका अनुसरण करते हुए सरकार न्यूनत आयु तय करने का विचार कर रही है। आंकड़ों को देखे तो देश में 14-16 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चे इस समय स्मार्ट फोन के समुद्र में डूबे हुए है। यह एक गंभीरतम स्थिति है।

आज घर घर में बच्चे और युवा धड़ल्ले से मोबाइल पर स्क्रीनिंग कर रहे है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है की यह उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए कितना खतरनाक है। मीडिया में छोटे और किशोर आयु के बच्चों को मोबाइल लत के खतरे से लगातार अगाह किया जा रहा है। अनेक बच्चे इसके दुष्परिणामों के शिकार होकर अस्पतालों में अक्सर का इलाज करा रहे हैं। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने देश में गत वर्ष मोबाइल पर 1.12 ट्रिलियन घंटे स्क्रीनिंग की गई जो दुनियाभर में सर्वाधिक आंकी गई है। इससे पता चलता है 18 वर्ष की आयु सीमा के 4० करोड़ बच्चे में से हर तीसरा बच्चा

एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था सेपियनलैब्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, कम उम्र में जब बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाते हैं तो युवावस्था आते-आते उनके दिमाग पर विपरीत असर दिखने लगता है। यह रिपोर्ट 40 देशों के 2,76,969 युवाओं से बातचीत करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन दिए गए, उनमें आत्महत्या के विचार, दूसरों के प्रति गुस्सा, सच्चाई से दूर रहना और हेलोसिनेशन होना शामिल है।

से बच्चों के मार्क्स में 1० फीसदी तक कमी आई है। एक अन्य रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 73 प्रतिशत स्कूली बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं। वहीं, 80 प्रतिशत बच्चे रोजाना सोशल मीडिया पर कम से कम 2 घंटे बिताते हैं। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर पड़ रहा है। मोबाइल आपका दोस्त है या दुश्मन। बिना विलंब किए इस पर गहवता से मंथन की जरूरत है। आजकल मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। एक स्टडी रिपोर्ट में एक बार फिर मोबाइल के खतरे से सावचेत किया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है पैरेंट्स बिना सोचे-समझे सिर्फ दो-ढाई साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। इसके बाद बिना मोबाइल यूज किए बच्चा खाना तक नहीं खाता है। हालांकि इंफॉर्मेशन, टेक्नोलोजी और एआई के दौर में मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? अगर आप भी मोबाइल एडिक्शन को सौरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आपको बता दें कि सेलफोन आपके बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। कच्ची उम्र में बच्चों को डिजिटल डिमेंशिया जैसी घातक बीमारी हो सकती है। टाइम ज्यादा होने का सबसे पहला असर बच्चों की आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। स्क्रीन को नजदीक और एक्टक देखने से आंखें ड्राई होने लगती हैं यही हालात रहने पर आंखों की रोशनी कम होने लगती है। मोबाइल बच्चों का दोस्त है या दुश्मन। बिना विलंब किए अभिभावकों को इस पर गहवता से मंथन की जरूरत है।

जब से इंटरनेट हमारे जीवन में आया है तबसे बच्चे से बुजुर्ग तक आभासी दुनिया में खो गए हैं। हम यहाँ बचपन की बात करना चाहते है। देखा जाता है पांच साल का बच्चा भी आँख खोलते ही मोबाइल पर लपकता है। पहले बड़े इसे अपने काम के लिए करते थे। अब बच्चे भी इंटरनेट के शौकीन होते जा रहे हैं। बाजार ने उनके लिए भी इंटरनेट पर इतना कुछ दे दिया है कि वह पढ़ने के अलावा बहुत कुछ इंटरनेट पर करते रहे हैं। पैरेंट्स को बच्चों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और समय रहते उनकी ऐसी आदत को पॉजिटव तरीके से दूर करना चाहिए।

—अतिथि संपादक,
बालमुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार



महावीर सिंह

बहुत से लोगों को 2०12 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुई विभत्स घटना याद होगी। दिल्ली में आम लोगों ने, मीडिया ने, विभिन्न नागरिक-युवा संगठनों ने इतने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया कि परिणाम स्वरूप उस लड़की को बढिया से बढिया इलाज उपलब्ध करवाया गया। त्वरित गति से मुकदम्मा दर्ज हुआ, शौभ्रता व सावधानी पूर्वक मुकमल जांच पूरी हुई और दोषियों को सख्त सजा मिली।

इस घटना ने, अपवादस्वरूप ही सही दिल्ली के सत्तासीनों के जमीर को भी हिला कर रखा दिया। परिणाम स्वरूप जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में इस घटना के परिपेक्ष में महिला के साथ होने वाली इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे, इसलिए कानूनों का पुनरावलोकन भी करवाया, सुझाव मंगवाए और परिणाम स्वरूप महिलाओं के साथ आपराधिक छेड़छाड़ दुर्व्यवहार से सम्बंधीत कानूनों पर नए दृष्टिकोणों से विचार व परिवर्तन शुरू हुए। मुख्य बात यह है कि ड्रेगलित जनमानस के दबाव के चलते यह सब सम्भव हुआ।

इस घटना के विपरीत, महिला पहलवानों के साथ हुई सेक्सुअल हैरसमेंट की घटना के जो आरोप लगाए गए उन पर विचार करें।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ओरोविल, संविधान और राष्ट्रीय शिक्षानीति 2०2०



सूर्यप्रतापसिंह राजावत

21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस तारीख के पीछे एक इतिहास है। ऐतिहासिक महत्व यह है कि बांग्लादेश धर्म के आधार पर बनाया गया था, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने उर्दू को भाषा के तौर पर थोपने का विरोध किया। उन्होंने बंगाली भाषा की मांग की और आखिरकार बंगाली को उस देश की दूसरी राष्ट्र भाषा बनाने में जीत हासिल की। इस संघर्ष के दौरान बंगालियों ने दर्जनों लोगों को खो दिया। यूनाइटेड नेशंस ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है, ताकि बांग्लादेशियों के अपनी मातृभाषा के लिए किए गए बलिदान को याद किया जा सके। इसे 1999 के यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में मंजूरी दी गई थी और 2000

से यह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 21 फरवरी श्री अरविन्द की आध्यात्मिक सभ्योगी, श्रीमों के जन्मदिन की भी याद दिलाता है। उनके सपनों के प्रोजेक्ट की ओरोविल-उपानगरिके रूप में जाना जाता है। ओरोविल को 1966, 1968, 1970, 1983, 2007 में यूनेस्को के आम सम्मेलन का समर्थन प्राप्त हुआ है। ओरोविल को अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में भी जाना जाता है जहाँ 30 से अधिक देशों के लोग एक साथ रहते हैं। ओरोविल के निवासी अतिमानसिक योग का अभ्यास करते हैं। अतिमानसिक योग रूपतरण से संबंधित है। श्रीअरविन्द के अनुसार मानव विकासवादी प्रक्रिया में संक्रमणकालीन चरण से संबंधित है। मनुष्य अंतिम रचना नहीं है, मनुष्य के बाद सुपरमेंटल शक्ति का आविर्भाव होगा। श्री मों के निम्नलिखित शब्द ओरोविलके उद्देश्य और लक्ष्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं - हम किसी पंथ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। हम किसी भी सकारा के खिलाफ नहीं लड़ते हम बँटवारे, बेहोशी, अज्ञानता, जड़ता और झुट से लड़ रहे हैं। हम धरती पर एकता, ज्ञान, चेतना, सत्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन सभी चीजों से लड़ते हैं जो प्रकाश, शांति, सत्य और प्रेम की इस नई रचना के आने का विरोध करती

है। ओरोविल अपनी एक खास बात के लिए भी जाना जाता है कि यहां लोगों के बीच पैसे का लेन-देन नहीं होता। 28 फरवरी, 1968 को, ओरोविल के चार्टर को फ्रेंच में पढ़ा गया। इसके बाद, चार्टर को 16 भाषाओं में इस क्रम में पढ़ा गया: तमिल, संस्कृत, इंग्लिश, अरबी, चीनी, रशियन, स्पैनिश, स्वीडिश और तिब्बती। भारत के संविधान का पार्ट सात ऑफिशियल भाषा से जुड़ा है, जिसे चैप्टर एक में बांटा गया है, जो यूनियन -संघ की भाषा से जुा है। चैप्टर दो क्षेत्रीय-रीजनल भाषाओं से जुड़ा है। चैप्टर तीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह की भाषा से जुड़ा है। चैप्टर चार भाषा से जुड़े खास निर्देशों से जुड़ा है। भारत के संविधान के शेड्यूल आठ में 22 भाषाओं की लिस्ट है जो मल्टीलिंगुअलिज्म दिखाती है। यह जानना दिलचस्प है कि खासवत संशोधन अनुच्छेद 350ए प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा देता है।यह बताना जरूरी है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आर्टिकल 351 के तहत एक खास निर्देश है कि जहाँ भी वोकैबुलरी के लिए जरूरी जा जरूरी हो, उसे संस्कृत से लिया जाना चाहिए। दुनिया भर में हुई साइटिफिक स्टडीज से पता चला है कि बच्चे के विकास में मातृभाषा बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। इसलिए, इस खास पहलू को

बाद में संविधान सभा ने सराहा और यही बात भारत के संविधान में भी दिखाई देती है, यहाँ तक कि मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (एनइपी 2020) भी इसी का सपोर्ट करती है। एनइपी 2020 इस बात पर चिंता जताती है कि भारतीय भाषाओं पर सही ध्यान और देखभाल नहीं दी गई है, अकेले पिछले 50 सालों में देश ने 220 से ज्यादा भाषाएँ खो दी हैं। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को खतरे में घोषित किया है। कई बिना लिखी हुई भाषाएँ खत्म हो जाती हैं। इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति के भावों को बचाने या रिकॉर्ड करने के लिए कई ठोस कदम या उपाय नहीं किए जाते हैं। एनइपी 2020 में कहा गया है कि भारत की वे भाषाएँ भी जो ऑफिशियली ऐसी खतरे वाली लिस्ट में नहीं हैं, जैसे कि भारत के संविधान के आठवें शेड्यूल में 22 भाषाएँ, कई मोर्चों पर गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं को पढ़ाने और सीखने को हर लेवल पर स्कूल और हायर एजुकेशन के साथ जोड़ने की जरूरत है। भाषाओं को रेलिवेंट और वाइरेंट बनाए रखने के लिए, इन भाषाओं में टेक्स्टबुक,

वर्कबुक, वीडियो, नाटक, कविताएँ, नॉवेल, मैगजीन वगैरह सहित हाई-क्वालिटी लर्निंग और प्रिंट मटीरियल की एक रेगुलर स्ट्रीम होनी चाहिए। भाषाओं की वोकैबुलरी और डिक्शनरी में भी लगातार ऑफिशियल अपडेट होने चाहिए, जो बड़े पैमाने पर फैले, ताकि इन भाषाओं में सबसे नए मुद्दों और कॉन्सेप्ट पर असरदार तरीके से चर्चा की जा सके। दुनिया भर के देश इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियन और जापानी जैसी भाषाओं के लिए ऐसे लर्निंग मटीरियल, प्रिंट मटीरियल और दुनिया की भाषाओं से जरूरी मटीरियल का ट्रांसलेशन, और वोकैबुलरी को लगातार अपडेट करने का काम कर रहे हैं। हालाँकि, भारत अपनी भाषाओं की पूरी इमानदारी के साथ सबसे अच्छे तरीके से वाइब्रेंट और कंटेंट रखने में मदद करने के लिए ऐसे लर्निंग और प्रिंट मटीरियल और डिक्शनरी बनाने में काफी धीमा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीन-भाषा फ़ॉर्मूले को जल्दी लागू करने, जहाँ तक हो सके घर/लोकल भाषा में पढ़ाने, और ज्यादा एक्सपीरियेंशियल भाषा सीखने का इंतजाम किया गया है।

—सूर्यप्रतापसिंह राजावत,
सचिव, श्री अरविन्द
सोसाइटी राजस्थान

विश्व मातृभाषा दिवस-2026

समृद्ध और समर्थ राजस्थानी भाषा को कब मिलेगा मान्यता का सम्मान



राजेन्द्र जोशी

विश्व मातृभाषा दिवस मतलब की मातृभाषाओं को पल्लवित और पोषित करने का समय माना जाता है। इस दिन विश्वभर की मातृ भाषाओं के ही हिमायती अपनी-अपनी मातृभाषा को समर्थ साबक करने का प्रयास करते हैं। सभी मातृभाषाएं सांस्कृतिक महत्व और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। भाषाओं को पोषित करने का काम संबंधित सरकार का रहता है। हम राजस्थानी समुदाय के लोग राजस्थानी भाषा को जीते हैं और संकल्पित होकर भाषाई दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं। भाषा व्यक्ति की पहचान होती है।

राजस्थानी भाषा समृद्ध भाषा है, इसका विपुल साहित्य भंडार है, यह करोड़ों लोगों की कंठहार है, विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर महामान मदनमोहन मालवीय, इतालवी विद्वान डा.एल.पी. टैस्तीटोरी, सुप्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. सुनीति कुमार चाटुर्जा सहित विश्व के ख्यातमान विद्वानों ने राजस्थानी भाषा एवं इसके समुन्नत समृद्ध साहित्य की प्रशंसा की है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता हेतु राजस्थान विधान सभा में लिए गए सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव वर्ष 2००3 में केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका है किन्तु अब तक राजस्थानी भाषा अपनी संवैधानिक मान्यता हेतु प्रतीक्षारत है। राजस्थानी भाषा को 8 वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों से सम्पूर्ण राजस्थानियों द्वारा प्रदेश व प्रवास से जोर-शोर से उठाई जाती रही है। जनगणना 2०11 में भी राजस्थान के 4 करोड़ 83 लाख लोगों ने अपनी मातृ भाषा राजस्थानी दर्ज कराई है। प्रवासी राजस्थानियों की संख्या भी कम नहीं है। घूमर लोकनृत्य को दुनिया के टॉप 1० स्थान मिलना, कालबेलिया नृत्य को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया जाना, प्रधानमंत्री जी के जापान दौरे में विदेशी कलाकारों ने भी राजस्थानी लोक गीत की प्रस्तुती, अमेरिका की लाईब्रेरी

राजस्थानी भाषा समृद्ध भाषा है, इसका विपुल साहित्य भंडार है, यह करोड़ों लोगों की कंठहार है, विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर महामान मदनमोहन मालवीय, इतालवी विद्वान डा.एल.पी. टैस्तीटोरी, सुप्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. सुनीति कुमार चाटुर्जा सहित विश्व के ख्यातमान विद्वानों ने राजस्थानी भाषा एवं इसके समुन्नत समृद्ध साहित्य की प्रशंसा की है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता हेतु राजस्थान विधान सभा में लिए गए सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव वर्ष 2००3 में केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका है किन्तु अब तक राजस्थानी भाषा अपनी संवैधानिक मान्यता हेतु प्रतीक्षारत है। राजस्थानी भाषा को 8 वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों से सम्पूर्ण राजस्थानियों द्वारा प्रदेश व प्रवास से जोर-शोर से उठाई जाती रही है। जनगणना 2०11 में भी राजस्थान के 4 करोड़ 83 लाख लोगों ने अपनी मातृ भाषा राजस्थानी दर्ज कराई है। प्रवासी राजस्थानियों की संख्या भी कम नहीं है। घूमर लोकनृत्य को दुनिया के टॉप 1० स्थान मिलना, कालबेलिया नृत्य को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया जाना, प्रधानमंत्री जी के जापान दौरे में विदेशी कलाकारों ने भी राजस्थानी लोक गीत की प्रस्तुती, अमेरिका की लाईब्रेरी

ऑफ कांग्रेस द्वारा राजस्थानी दुनिया की तेरह समृद्धतम भाषाओं में शुमार किया जाना, अमेरिका की शिकागो, रूस की मुस्को, लंदन की कैब्रिज के समान श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में राजस्थानी का अध्ययन-अध्यापन, अमेरिका सरकार की नौकरियों के लिए राजस्थानी को मान्यता दिए जाने सहित कई ऐसे प्रमाण हैं जो राजस्थानी को समृद्ध और बड़े समुदाय की भाषा ठहराते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस पर हम निम्नप्र अग्रुधर करते है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता हेतु केन्द्र सरकार शीघ्र निर्णय ले कर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाए। मुक्ति संस्था,बीकानेर द्वारा एक दशक पहले नवंबर 2०16 में प्रारंभ की गई राजस्थानी भाषा मान्यता संकल्प यात्रा के दौरान यह तथ्य भी सामने आए जब बंगाल, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में भाषा मान्यता संकल्प यात्रा लोगों से खूबक हुई। हजारों लोगों ने गत एक दशक के राजस्थानी भाषा मान्यता के पक्ष में हस्ताक्षर कर समर्थन देते हुए केंद्र सरकार से इस भाषा को मान्यता देने की मांग रखी। मुक्ति संस्था बीकानेर द्वारा भाषा मान्यता आंदोलन सतत रूप से जारी है। राजस्थान-राजस्थानियों को विश्वास है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की

आठवीं अनुसूची में शामिल करने का पुनित एवं ऐतिहासिक काम केन्द्र सरकार करेगी। राजस्थानी भाषा की मान्यता का आंदोलन 1944 में दीनापुर सम्मेलन से प्रारंभ हुआ था। राजस्थानी भाषा को मान्यता का आश्वासन सरकारों द्वारा दिया तो जाता रहा है लेकिन मान्यता देने में सरकार संदेव पीछे रही है। राजस्थानी भाषा 12०0 वर्षों से पुरानी है और इस भाषा का विशाल शब्दकोश जो अन्य भाषाओं से भी बहुत बड़ा है। इस शब्दकोश में लगभग दो लाख बड़ा शब्द विश्व विज्ञमान है। जबकि छोटी भाषाओं को सरकार ने मान्यता दे रखी है। राजस्थानी भाषा को राजनैतिक कारण से मानता नहीं देना यह हजारों राजस्थानियों का अपमान है। भारत सरकार ही ऐसा करने में सक्षम है। इस ऐतिहासिक काम के लिए संपूर्ण राजस्थान और राजस्थानी समाज चिकला आभारी रहेगा और इस फैसले से माननीय सर्वत्र सरहना के भागीदार होंगे। विश्व मातृभाषा दिवस हमें हमारी भाषा के प्रति सम्मान सम्मान के संकल्प को याद दिलाता है। हम इस अवसर पर राजस्थान सरकार से भी आग्रह करते हैं की राजस्थानी भाषा को दूसरी राजभाषा बनाने की घोषणा करें।

—राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद्-साहित्यकार



पंडित अनिल शर्मा

लाभ-अमृत 2:०5 से 4:54 तक।

राहूकाल: 9:०0 से 1०:30 तक। सूर्योदय 7:03, सूर्यास्त 6:18

मेघ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अंगणल कार्यों में खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। नौकरों/पेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कुंभ
अपने अति आवश्यक कार्यों में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। प्रयास करें। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में आ रही परेशानियों दूर होने लगेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

जल महल पर सूर्य किरण और सारंग ने हैरतअंगेज करतबों से किया रोमांचित

आसमान में सधे हुए अंदाज़ में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाई और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स का प्रदर्शन किया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । जयपुर में शुक्रवार को जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित ब्रांड एंबेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरतअंगेज करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उपस्थिति रही। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

जल महल की पाल से खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने पांच रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। आसमान में सधे हुए अंदाज़ में उड़ते हेलिकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएँ बनाई और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

हेलिकॉप्टरों की सटीक दूरी, संतुलन और तालमेल भारतीय वायु सेना के अनुशासन एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण रहा, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की।

इसके पश्चात जब लाल-सफेद रंग के आकर्षक एचएडब्ल्यूके एमके-१32 जेट विमानों ने उड़ान भरी तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गुंज उठा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाईंग तथा लोकप्रिय ‘डीएनए’ संरचना जैसे



जयपुर में शुक्रवार को जल महल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ।

जटिल और रोमांचक करतबों का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में लहराते तिरंगे रंगों ने दर्शकों के मन में गर्व और देशभक्ति का भाव भर दिया।

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के तीन प्रतिभाशाली पायलट विंग

कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्व्वाइन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही निवासी हैं। अपने गृह नगर में साहस, हुनर और कौशल का प्रदर्शन करना उनके लिए विशेष गौरव का क्षण रहा। दर्शकों ने जांबाज पायलटों के सम्मान में खड़े

होकर तालियों से उनका अभिनंदन किया।

यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणास्रोत बना। कार्यक्रम ने उनमें देशभक्ति, साहस और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह का संचार किया। बड़ी

संख्या में विद्यार्थियों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। रविवार को जल महल पर एरोबैटिक डिस्प्ले का मुख्य एवं विस्तृत आयोजन किया जाएगा, जिसमें और भी भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे।

181 हैल्पलाइन पर 35 आईएसएस सुनेंगे समस्याएं

जयपुर (कासं)। प्रदेश में आमजन की शिकायतों के समय पर निपटारे को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 35 वरिष्ठ आईएसएस अधिकारियों को राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 पर सीधे ड्यूटी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सचिव से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारी अब सचिवालय स्थित कॉल सेंटर में बैठकर खुद लोगों के फोन उठाएंगे। प्रत्येक अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 10 कॉल रिसीव करेगा और समस्याओं का यथासंभव त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संपर्क पोर्टल पर दर्ज पुरानी लंबित शिकायतों में से कम से कम 10 मामलों का चयन करें, जिनका समाधान आसानी से संभव है लेकिन वे लंबे समय से अटक हुए हैं। इन मामलों का निस्तारण कर संबंधित व्यक्तियों को जवाब देना अनिवार्य होगा। अक्सर प्रमाण पत्र जारी करने, बिजली-पानी आपूर्ति, सफाई और अन्य बुनियादी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें लंबित रहती हैं, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं भी 181 कॉल सेंटर का दौरा कर रहे हैं और आमजन से सीधे संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रमों में भी शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया जा रहा है।

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण : मुख्यमंत्री का कांग्रेस का प्रयास निंदनीय’

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के प्रतिष्ठित और गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के आचरण को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी प्रगति, नवाचार क्षमता और उज्ज्वल भविष्य की सराहना कर रहा है, उस समय कांग्रेस द्वारा देश की छवि को धूमिल करने का यह प्रयास निंदनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट

■ कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्रिहत से ऊपर रखा : भजनलाल शर्मा

में विश्वभर से आए विदेशी प्रतिनिधि, निवेशक और दिग्गज तकनीक विशेषज्ञ भारत की बढ़ती वैश्विक साख, डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उभरती नेतृत्वकारी

भूमिका पर सकारात्मक चर्चा कर रहे थे। ऐसे अवसर पर भी कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मंच से देश की छवि को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का यह रवैया नया नहीं है। कांग्रेस ने व्यापार समझौतों पर भ्रम फैलाने से लेकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और गलतबान में वीरता दिखाने वाले सैनिकों के शौर्य पर प्रश्नचिह्न लगाने तक, अनेक अवसरों पर राष्ट्रिहत से ऊपर अपने राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा

कि आज कांग्रेस ने करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती दी है। भारत की प्रतिष्ठा किसी दल की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक अस्मिता से जुड़ी है। इसे आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व को बिना विलंब देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जनता कांग्रेस को इस नकारात्मक और अवसरवादी राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

इंटर डिस्कॉम तबादलों पर बनेगी उच्च स्तरीय समिति

जयपुर (विसं)। प्रदेश के पावर सेक्टर में इंटर डिस्कॉम तबादलों के मुद्दे पर सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए ऊर्जा राज्यमंत्री हिरालाल नागर ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित स्थानांतरण संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी।

कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों की खामियों को उजागर किया था।

उन्होंने सदन में कांग्रेस को खुली चुनौती दी थी कि, वे अपने 2 वर्ष के कार्यकाल और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर चर्चा करने को तैयार हैं। इसके बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में इसकी व्यवस्था दी थी।

आमेर मावठे में नौका विहार का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक

20 वर्षों के इंतजार के बाद गुलाबी नगरी में पुनः शुरू हुई व्यवस्था

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । विश्व प्रसिद्ध आमेर महल की तलहटी स्थित मावठा सरोवर में करीब दो दशक बाद फिर से बोटिंग सेवा शुरू की जा रही है। लगभग 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यहां ट्रायल संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जिससे आमेर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। परियोजना प्रभारी सुमित सिंह ने बताया कि 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे से ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल चल रहा रहे पर इसी दिन से आम पर्यटकों के लिए आधिकारिक संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। बोटिंग संचालन का अनुबंध पर्यटन विभाग ने जसराज इंग्रू को दिया है। कंपनी ने सरोवर पर दो जेटी स्थापित की हैं।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 25 पैडल बोट, 5 कश्मीरी शैली की शिकारा, 20 सीटर और 30 सीटर लम्जरी बोट संचालित की जाएंगी। 30 सीटर लम्जरी बोट विशेष आकर्षण रहेगी, जबकि हैरिटेज लुक वाली नावें भी जन्द शामिल की जाएंगी। किराया दरें शीघ्र घोषित की

जाएंगी। वहीं अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा मानकों, जेटी प्रबंधन और रेस्क्यू सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। सभी पर्यटकों को लाइफ जैकेट दी जाएगी तथा प्रशिक्षित नाविक, गोताखोर और रेस्क्यू बोट तैनात रहेंगी। हरी-भरी अरावली पहाड़ियों के बीच शांत जल में आमेर महल का प्रतिबिम्ब और तैरती नावें पर्यटकों को विशेष अनुभव देंगी। पर्यटन विभाग ने कालबेलिया नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और भविष्य में लाइट एंड साउंड शो की भी योजना बनाई है। सरोवर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पर्यटकों के लिए बोटिंग करने का किराया भी जन्द तय किया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित नाविक और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही मावठा सरोवर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।



आमेर महल की तलहटी स्थित मावठा सरोवर में करीब दो दशक बाद फिर से बोटिंग सेवा शुरू की जा रही है। लगभग 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यहां ट्रायल संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

आयकर छापेमारी में कान्हा ग्रुप के पास मिली करोड़ों रु. की ज्वैलरी

आयकर टीम को खुफिया स्ट्रॉन्ग रूम मिले जेवरात, एक करोड़ रु. नकद सहित 10 लॉकर चिन्हित

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध फूड चैन कान्हा रेस्टोरेंट समूह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) की कार्रवाई शुक्रवार तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार सुबह शुरू हुई इस समन्वित छापेमारी में जयपुर सहित छह शहरों और मुंबई तक फैले 33 ठिकानों पर सचं किया जा रहा है। जयपुर में सर्वाधिक 26 परिसरों-कार्यालय, गोदाम और अन्य प्रतिष्ठानों-की जांच चल रही है।

आयकर विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान एक ठिकाने पर दीवार के पीछे बना खुफिया कक्ष मिला। संदेह होने पर दीवार तोड़ी गई तो भीतर मजबूत स्ट्रॉन्ग रूम मिला। जहां से करीब पांच करोड़ रुपये मूल्य की

■ **शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कान्हा ग्रुप के 33 ठिकानों पर छापेमारी जारी रही**

ज्वैलरी बरामद हुई। सरकारी मूल्यांकनकर्ता आभूषणों का आंकलन कर रहे हैं। अब तक करीब एक करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए जा चुके हैं। उससे यह साफ है कि यह टैक्स चोरी का आंकड़ा 100 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा।

इसके अलावा आयकर टीम को 10 बैंक लॉकरों की और जानकारी मिली है, जिन्हें खुलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार

लॉकरों में बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और सोना मिलने की आशंका है। सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग की जांच का दायरा रेस्टोरेंट कारोबार से आगे बढ़कर रियल एस्टेट निवेश तक पहुंच गया है। आमेर स्थित ताज होटल और कूकस के कुंदन वन होटल में निवेश की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। विभाग को संदेह है कि लाघ कम दिखाकर धन को आलीशान संपत्तियों में लगाया गया। आयकर टीमें बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड, नकद लेन-देन, प्रॉपर्टी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गहन जांच कर रही हैं। बड़ी मात्रा में फाइलें व डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी आगे भी जारी रहने की संभावना है।

रैलिंग तोड़कर स्कॉर्पियो में घुसी लोहे की राँड

जयपुर (कासं)। मुरलीपुरा क्षेत्र में शुक्रवार अलसुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बनी लोहे की रैलिंग और जाली तोड़ते हुए उसमें जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोहे का एंगल वाहन का शीशा चीरता हुआ चालक के सीने में जा घंसा।

हैड कांस्टेबल रविंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में आनंद सिंह शेखावत (28) निवासी सुंदर विहार कर्धनो की मौत हुई है। वह स्कॉर्पियो चला रहा था। उसके साथ उसका दोस्त शक्ति प्रताप (22) निवासी मुरलीपुरा बैठा था। जो इस हादसे में बाल-बाल बच गया। प्रार्थिक जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त गुरुवार रात किसी कार्य से निकले थे।

रात करीब 2:40 बजे दादी का फाटक से मुरलीपुरा की ओर जाते समय केडिया चौराहे के पास वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह रैलिंग से जा टकराया। सूचना पर मुरलीपुरा थाना पुलिस और दुर्घटना थाना पश्चिम की टीम मौके पर पहुंची।

किरोड़ीलाल को हैसियत के अनुरूप पद नहीं मिला : रामकेश मीणा

सदन में उपनेता प्रतिपक्ष ने मंत्री किरोड़ीलाल की तारीफ में कसीदे गढ़े

जयपुर (विसं)। कांग्रेस विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने विधानसभा में डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ करते हुए कई टिप्पणियां कीं, जिससे सदन का माहौल गरमा गया। जिस पर सभापति ने आपत्तिजनक टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने के निर्देश दिए।

रामकेश मीणा ने अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कहा कि, डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा के लिए काफी काम किया, लेकिन उन्हें उनकी हैसियत के अनुरूप पद नहीं मिला। उन्हें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या गृहमंत्री बनाया जाना चाहिए था।

इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं डॉ. किरोड़ी गंगापुर से चुनाव न लड़ लें, इसलिए उनकी तारीफ की जा रही है। जवाब में रामकेश मीणा ने कहा कि डॉ. किरोड़ी उनके समाज के बड़े नेता हैं और यदि वे गंगापुर से चुनाव लड़ते हैं तो वे स्वयं सीट खाली करने को तैयार हैं। रामकेश मीणा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा को खड़ा करने में डॉ. किरोड़ीलाल की बड़ी भूमिका रही है और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पार्टी को उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

■ **मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने चुटकी लेते हुए कहा कि “कहीं डॉ. किरोड़ी गंगापुर से चुनाव न लड़ लें, इसलिए उनकी तारीफ की जा रही है।” जिसके जवाब में रामकेश मीणा ने कहा कि डॉ. किरोड़ी उनके समाज के बड़े नेता हैं और यदि वे गंगापुर से चुनाव लड़ते हैं तो वे स्वयं सीट खाली करने को तैयार हैं।”**

रामकेश ने कहा कि भाजपा पर जब भी कोई संकट आया तो इस बीजेपी को संकट से निकलने का काम किसी ने किया तो उसका नाम डॉ. किरोड़ी लाल मीणा है। ईआरसीपी को लेकर डूंगरी बांध का मामला चल रहा है। जहां आंदोलन में लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी का एक व्याक्ति डूंगरी बांध आंदोलनकारियों के

बीच जाकर अपनी बात कह दे, तो मान लूंगा। आप किरोड़ीलाल मीणा को भेजेंगे, वहां बैठने के लिए कहेंगे। लेकिन जब अधिकार लेने के बात आती है तो उन्हें आखिरी पंक्ति में बैठा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल लाल मामूली व्यक्ति नहीं है, क्या समझ रहे हो भाजपा की ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगा तो वह किरोड़ीलाल मीणा है। आपने उनकी सारी शक्तियां छीन ली।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि किरोड़ीलाल को कौन सी शक्ति नहीं दी, यह कौन सी डिमांड है? जोरेश्वर गंज ने कहा दासा में उपचुनाव हुए तब भूल क्यों गए थे, किरोड़ी को क्यों हारे ? बहस के दौरान हुई तीखी टिप्पणियों से सदन का माहौल गरमा गया, हालांकि बाद में सभापति ने कार्यवाही से बाहर निकालने के निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक अश्वण कुमार ने कहा कि सदन में जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए लेकिन रोटी गूलल से डाउनलोड नहीं हो सकती। किसानों के ऋण वितरण समय पर होने चाहिए। ऋण माफ कर किसानों को परजीवी मत बनाओ। इसका स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए।

सीवरेज प्लांट्स पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट

यूडीएच मंत्री खर्ग ने अपने जवाब में इन प्रोजेक्ट्स की देरी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान विधानसभा में प्रदेश में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अधूरे कार्यों को लेकर पूछे गए सवाल पर हंगामा हो गया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्ग के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने प्रश्न उठाया कि शहरों में व्यापक खुदाई की गई है, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम अब भी अधूरे हैं। उन्होंने पूछा कि इन ट्रिटियों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जलाई और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने

■ **मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू कर दिया, स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने अगला प्रश्न ले लिया। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए।**

परियोजनाओं में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की शर्तों का पालन नहीं हुआ। सीवरेज पाइपलाइन डालते समय इनलेट और आउटलेट का स्तर सही नहीं रखा गया, जिससे तकनीकी दिक्कतें आईं। उन्होंने पूछा कि इन ट्रिटियों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जलाई और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने

अगला प्रश्न ले लिया। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए।संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के रविये की निंदा करते हुए कहा कि अनुकूल जवाब नहीं मिलने पर वॉकआउट करना उचित नहीं है। वहीं बसपा विधायक मनोज न्यांगली ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि हंगामे और वॉकआउट से अन्य सदस्यों का समय प्रभावित होता है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में “राज-उन्नति” की बैठक को वीसी के माध्यम से संबोधित किया।

‘कार्मिक पूरी निष्ठा से दायित्य निभाएं, लापरवाही हुई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी’

‘कार्मिक पूरी निष्ठा से दायित्य निभाएं, लापरवाही हुई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी’सब हैडिंग-24-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज उन्नति की बैठक को संबोधित करते हुए चेतावनी दी

जयपुर, 20 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जन सेवा को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रही है। अधिकारी जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्मिक पूर्ण निष्ठा से अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में “राज-उन्नति” की बैठक को वीसी के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की 84 हजार 282 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और योजनाओं पर चर्चा की तथा अधिकारियों को इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

मुख्यमंत्री शर्मा ने पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता के साथ, समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने

एआई सम्मेलन स्थल पर कांग्रेस का प्रदर्शन

नई दिल्ली, 20 फरवरी। राजधानी में एआई इम्पैक्ट सम्मेलन स्थल पर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले में व्यापक साजिश की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान आरोपितों की सुरक्षा कर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ लंबी धक्का-मुक्की हुई। इसी दौरान प्रदर्शनी कक्ष के भीतर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ी साजिश थी।

जानकारी के मुताबिक, सम्मेलन स्थल के प्रदर्शनी कक्ष संख्या-5 के भीतर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने ‘टी शर्ट उतार कर’ प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट लहराई, जिससे परिसर में हंगामा खड़ा हो गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले लेबर की 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उन्हें तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। पुलिस अपने संबोधन में हेलबर्ग ने बड़ते आर्थिक दबाव और साइबर खतरों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमजोरियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “हम देख रहे हैं कि हमारे मित्र और सहयोगी रोज आर्थिक दबाव और ब्लैकमेल की धमकियों का सामना कर रहे हैं, जहाँ उन्हें अपनी संप्रभुता और समृद्धि के बीच चुनाव करने को मजबूर किया जाता है।” उन्होंने आगे कहा, “हमने देखा है कि सीमा पर से एक की-स्टोकि के जरिए एक महान भारतीय शहर की बर्तियों बुझा दी गईं...।”

हेलबर्ग की संभवतः मुंबई ब्लैकआउट की ओर संकेत कर रहे थे, जिसे व्यापक रूप से चीनी साइबर चुसपैउ से जुड़ा माना गया था। पैक्स सिलिका घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में आयोजित एआई

- राज उन्नति मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरु की गई पहल है. इसमें चयनित परियोजनाओं व कार्यों पर चर्चा की जाती है। मुख्य सचिव ने राज उन्नति की पहली बैठक के निर्देशों की रिपोर्ट भी पेश की।**

765 केवी डी/सी ब्यावर-दौसा ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित कार्य में गति लाने और 765 केवी डी/सी सीकर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लाइन को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। शर्मा ने उद्योग विभाग को भीलवाड़ा में बन रहे टेक्सटाइल पार्क में समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए भूखण्ड आवंटन प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में आरएफआईडी एवं जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली को चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव पाक्षिक रूप से बैठक करें।

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की जिला कौशल समितियों

को और अधिक सक्रिय करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत, महिलाओं एवं बालिकाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण के लिए वितरण केंद्रों पर सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा 5 साल में 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि गत वर्ष की लॉबित बजट

घोषणाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ‘एक जिला-एक उत्पाद’ नीति के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

इस दौरान मुख्य सचिव ने राज उन्नति की प्रथम बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज उन्नति की पहल की गई है। इसमें चयनित परियोजनाओं, योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत चर्चा कर प्रदेश के विकास को गति दी जा रही है। इसमें आमजन से जुड़े कार्यों और परिवेदनाओं को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। जैसलमेर के धनाराम सहित, अन्य परिवारद्वि में मुख्यमंत्री का समस्याओं के समाधान के लिए आभार जताया। बैठक में वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव तथा जिला कलक्टर्स जुड़े।

एक अप्रैल से सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही कटेगा टोल टैक्स

नई दिल्ली, 20 फरवरी। केन्द्र सरकार ने देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतना बंद करने का ऐलान किया है। देश में एक अप्रैल से टोल शुल्क केवल

- केन्द्रीय सड़क परिहहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक देशभर में 1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी।**

फास्टैग या यूपीआई से ही लिया जाएगा। केन्द्रीय सड़क परिहहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में 1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी। यह पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत तकनीक-आधारित, तेज और निर्बाध राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

‘मां बाप को बताए बिना शादी नहीं कर पाएंगे गुजरात में’

अहमदाबाद, 20 फरवरी। गुजरात में अब चुपके से या घरवालों को बताएबिना शादी करना आसान नहीं होगा। गुजरात विधानसभा में आज मैरिज रजिस्ट्रेशन के नए नियमों की घोषणा हुई है। इस नियमों ने यह साफ कर दिया है कि अब हर शादी से पहले माता-पिता को अनिवार्य रूप से बताया जाएगा। यानी भागकर शादी करने

- गुजरात सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में इस सम्बंध में बदलाव करने जा रही है।**

वाले कपल्स के लिए यह प्रस्तावित बदलाव एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। सरकार ने इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम 44 में भी बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। गुजरात सरकार ने इसे जnahित का मुद्दा बताया गया है। इस बदलाव का मुख्य हिस्सा किसी भी शादी से पहले माता-पिता को सूचना देना और माता-पिता को जानकारी जमा करना है। इसे शादी रजिस्टर करने की कानूनी प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। प्रस्तावित नियमों में पूरी प्रक्रिया को कागजी रिकॉर्ड से हटाकर एक राज्य सरकार के सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रांसफर किया जाएगा।

फिर से राजस्थान हाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कराओ, दोपहर 12 बजे तक हाईकोर्ट खाली कर दो, यहां आरडीएक्स प्लांट किया गया है। इस सूचना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और आनन-फ़ानन में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। पिछले चार महीनों में 10वां अवसर है, जब कोर्ट को डराने की कोशिश की गई है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज के अनुसार, धमकी मिलते ही बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। कोर्ट रूम से लेकर पार्किंग तक चप्पा-चप्पा छाना गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब

‘मेरे नाम से ही आए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तब यह कई लोगों को असंभव लगता था। आज सबजीवाला ऑनलाइन पैसा ले रहा है। यहां तक कि पहले की तरह घर से निकलने पर पैसा संभाल कर रखने की जरूरत भी खत्म हो गई है, लेकिन

यूपी के बाल

बांदा, 20 फरवरी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में नाबालिग बच्चों के साथ हुए संगठित यौन शोषण के अत्यंत गंघन्य मामले में विशेष न्यायालय पाँक्सो एक्ट, बांदा ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मुख्य दोषी निलम्बित जेई राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक सौरभ सिंह के अनुसार, इस मामले की जांच सीबीआई, दिल्ली द्वारा की गई थी। इसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में दर्ज की गई थी। अभियोजन पथ की ओर से विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह ने दोषियों को प्रभावी पैरवी की। जांच में सामने आया कि आरोपित दम्पति, जो थाना नरैनी क्षेत्र के निवासी हैं, ने चित्रकूट में किराये के

ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को आरएएफ एयरबेस नहीं देगा ब्रिटेन

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की इस घोषणा से डॉनल्ड ट्रंप भारी गुस्से में हैं

- ट्रंप ने स्टार्मर के उस समझौते को समर्थन देने से इन्कार कर दिया जिसके तहत चागोस द्वीप मॉरीशस को सौंपने की प्रक्रिया चल ? रही थी।**

आरएएफ फेयरफोर्ड (ब्रिटेन) का इस्तेमाल करना चाहता है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और 1970 के दशक से यह ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य अड्डा है। यह ठिकाना रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहां से एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व तक लंबी दूरी के सैन्य अभियान संचालित किए जा सकते हैं। ब्रिटेन के पुराने रक्षा समझौतों के अनुसार, उसके किसी भी सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अनुमति आवश्यक होती है। अंतरराष्ट्रीय कानून

‘एआई सूनामी जैसा है, दुनियाभर में इससे 40 प्रतिशत नौकरियां प्रभावित होंगी’

- इन्टरनैशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) “सुनामी की तरह” है, जो वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित करेगी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह असर 60 प्रतिशत तक हो सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बोलेते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि प्रवेश-स्तर (एंट्री-लेवल) की नौकरियां सबसे अधिक जोखिम में हैं और सरकारों से तत्काल नीतिगत कदम उठाने का आग्रह किया।**

उन्होंने भारत के डिजिटल सुधारों की सरहना करते हुए अनुमान जताया कि एआई भारत की वार्षिक आर्थिक

यौन शोषण कांड में दो दोषियों को फांसी

- पाँक्सो कोर्ट ने यह एतिहासिक फैसला सुनाया और आरोपी राम भवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई।**

- आरोप हैं कि दम्पति चित्रकूट में किराए के मकान में रहते थे उन्होंने 33 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया उनके दो लाख से ज्यादा वीडियो बनाकर विदेश भेजे।**

मकान में रहकर करीब 33 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के आपसिकता वीडियो बनाकर उन्हें विदेशों में भेजा। जांच एजेंसियों के अनुसार, लगभग 2 लाख से अधिक वीडियो तैयार कर करीब 47 देशों में भेजे गए, जिनका उपयोग ब्लैकमेलिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया गया। मुकदमे के

बंगाल में एसआईआर के लिए न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश जारी किया

- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हिंसा की कथित घटनाओं पर स्टेट्स रिपोर्ट भी मांगी है और चुनाव आयोग से 28 फरवरी तक संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित करने को कहा है।**

बंगाल में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हालत है, जहां दो संवैधानिक संस्थाएं निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों के बीच विश्वास की कमी साफ नजर आती है। इसके चलते एसआईआर प्रक्रिया अटक की हुई है। इस असाधारण हालात के चलते हमारे पास यह फैसला लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एसआईआर से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं, ऐसे में राज्य में वोटर्स की अंतिम सूची 28 फरवरी तक प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है।

के तहत भी यदि कोई देश यह जानते हुए कि सैन्य कार्रवाई अवैध या विवादित है, उसमें सहयोग करता है, तो उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस आईलैंड्स को लेकर ब्रिटेन की नीति की आलोचना की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्‌यु सोशल पर लिखा कि डिएगो गार्सिया जैसा महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। उनका तर्क है कि यदि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता, तो अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद इन एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ऐसे में इनका नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।

ब्रिटिश सरकार का कहना है कि मॉरीशस के साथ चागोस द्वीप समूह को लेकर किया गया समझौता सुरक्षा और कानूनी स्थिरता के लिहाज से आवश्यक है। लंदन का तर्क है कि यह कदम लंबे और महंगे अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवादों से बचने के लिए उठाया जा रहा है। अनुमान है कि पूरे समझौते की लागत करीब 3.5 बिलियन पाउंड तक पहुंच सकती है।

इन्टरनैशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यह भी कहा कि उन्नत देशों में एआई 60 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित करेगा।

ग्रोथ में 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकता है। समिट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि एआई को लेकर भारत का आशावाद पश्चिमी देशों से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े एआई प्रतिभा-भंडारों में से एक है।

(आपराधिक धमकी), 120 बी (आपराधिक साजिश), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी तथा पाँक्सो अधिनियम, 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत तौर सिद्ध किया। साथ ही मृत्युदंड के अलावा आजीवन कारावास, कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। न्यायालय ने सभी पीड़ित बच्चों की 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी पारित किया है। साथ ही जुर्माने की राशि भी पीड़ितों को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध में केवल बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं, बल्कि समाज की नैतिक नींव को भी हिला देते हैं। यदि ऐसे मामलों में कठोर दंड नहीं दिया गया, तो यह समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

^[1] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं॰ RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, खजुरी सिवार्ड मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नगर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

^[2] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं॰ RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, खजुरी सिवार्ड मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नगर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

^[3] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं॰ RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, खजुरी सिवार्ड मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नगर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

^[4] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं॰ RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, खजुरी सिवार्ड मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नगर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

^[5] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं॰ RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, खजुरी सिवार्ड मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नगर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

^[6] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं॰ RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, खजुरी सिवार्ड मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नगर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908